आर. एस. नरूला, रणजीत सिंह सरकार और एस. सी. मितल के समक्ष, जे.जे.

अमर चंद-अपीलार्थी.

बनाम।

हरजी, और अन्य,-प्रतिवादी। आर}

।960 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 1362

2 मार्च 1971.

पंजाब प्रथा (प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति) अधिनियम (II of 1920)- धारा 6-पंजाब पूर्व मुक्ति अधिनियम (1913 का I)-धारा 15-साक्ष्य अधिनियम (1872 का I)-धारा 115-सिविल प्रक्रिया संहिता (1898 का V)-धारा 11 और आदेश 2 नियम 2-विक्रेता के प्रत्यावर्तक द्वारा पूर्व-छूट के लिए मुकदमा खारिज-बिक्री को चुनौती देने वाला अगला मुकदमा, कस्टम के तहत, विचार के अभाव और कानूनी आवश्यकता के लिए -'क्या वर्जित है-लाभ सिंह बनाम गोपी और अन्य में निर्दिष्ट बहिष्कार, प्रतिनिर्णय या छूट का नियम (1)- क्या इसे पंजाब प्रथा के मूल नियम के रूप में देखा जाए-पैतृक संपत्ति के अलगाव को रोकने के लिए रिवर्सनर का अधिकार-की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि-कहा,

अभिनिर्धारित है की, कि ऐतिहासिक रूप से, रिवाज़ के तहत, पैतृक संपत्ति के अलगाव को रोकने के लिए एक प्रत्यावर्तक का अधिकार, स्वामित्व के अज्ञेय सिद्धांत का एक उत्पाद है, जिसके अनुसार स्वामित्व इकाई जनजाति थी जनजाति का व्यक्तिगत सदस्य केवल उस भूमि के उस हिस्से को हड़पने का हकदार था जो वास्तव में उसके और उसके परिवार द्वारा खेती की गई थी, और उस हिस्से में भाग लेने का हकदार था जो अभी भी संयुक्त प्रबंधन के तहत था। ऐसे समुदाय में, स्वामित्व का अधिकार और स्थायी रूप से सामान्य प्रणोदक को अलग करने की शक्ति पूरे शरीर में निहित थी। समय के साथ, जैसे-जैसे इन समुदायों ने अपने आदिम चरण को पीछे छोड़ दिया, आम भूमि या इसका एक बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से परिवारों के बीच विभाजित हो गया और परिवार स्वामित्व की इकाइयाँ बन गए। परिवार की भूमि हस्तांतरण या उप-विभाजन के परिणामस्वरूप व्यक्तियों के कब्जे में आ गई, लेकिन ऐसे किसी भी व्यक्ति के हाथों में पैतृक अचल संपत्ति के संबंध में 'सामान्य पूर्वज के सभी वंशजों में एक अवशिष्ट हित मौजूद था, भले ही उनमें से कुछ के कुछ समय के लिए धारक के उत्तराधिकारी होने की संभावना बहुत दूर थी।' हालांकि, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक अलगाव का मुकाबला करने के लिए एक प्रत्यावर्तक का यह अधिकार नागरिक के अनुबंध की स्वतंत्रता के सामान्य अधिकार के खिलाफ है, अदालतों ने इसकी कोणीयता के इस नियम को छीन लिया है और इसे वैध सीमाओं के भीतर सीमित रखा है। इस प्रकार, पंजाब में सार्वभौमिक प्रथा के बचे हुए नियमों में से एक, जो न्यायिक निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला द्वारा दृढ़ता से स्थापित किया गया है, यह है कि पैतृक अचल संपत्ति के अलगाव पर आपत्ति करने वाला उचित व्यक्ति तत्काल प्रत्यावर्ती उत्तराधिकारी है; और यदि वह, सद्भावना से, अलगाव में सहमत होता है, तो यह लेनदेन को मान्य करता है और इसे पंजाब के किसी भी वंशज द्वारा हमले से मुक्त करता है विचार की कमी और कानूनी आवश्यकता के आधार पर सामान्य पूर्वज।

माननीय न्यायमूर्ति एस. सी. मित्तल द्वारा 30 जुलाई, 1970 को मामले में शामिल विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए वृहद न्यायपीठ को निर्दिष्ट किया गया मामला। माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. एस. नरूला, माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. एस. सरकारिया और माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. सी. मित्तल की पूर्ण पीठ ने विधि के प्रश्न का विनिश्चय किया और 2 मार्च, 1971 को विधि के अनुसार निपटान के लिए मामले को एकल पीठ को लौटा दिया। माननीय श्री एस. सी. मित्तल ने अंततः 21 अप्रैल, 1971 को मामले का फैसला किया।

श्री जी. डी. जैन के न्यायालय के डिक्री से दूसरी अपील, बढ़ी हुई अपीलीय शक्तियों के साथ, हिसार, प्रथम श्रेणी उच्च न्यायालय 6 '1960 यह अभिकथन करते हुए कि श्री जगदीश वादी का मुकदमा 23 दिसंबर, 1959 को, वाद को लागत के साथ खारिज करते हुए।

सारकारिया, जे. -इस पूर्ण पीठ को राय के लिए संदर्भित प्रश्न यह हैः-"जहां एक प्रत्यावर्तक द्वारा दायर पूर्व-छूट के लिए एक मुकदमा खारिज कर दिया जाता है, क्या उसका बाद का मुकदमा उसी संपत्ति की बिक्री को चुनौती देता है, सीमा शुल्क के तहत, विचार और कानूनी आवश्यकता के अभाव में, वर्जित है?

इस आदेश की ओर ले जाने वाली परिस्थितियाँ यह हैं कि प्रतिवादी-प्रतिवादी 1, हरजी ने राम करण, प्रतिवादी/प्रतिवादी 2 को मुकदमे में जमीन बेच दी। उस बिक्री के संबंध में प्री-एम्पशन द्वारा कब्जे के लिए दो प्रतिद्वंद्वी मुकदमे दायर किए गए थे, एक विक्रेता के बेटे अमर चंद वादी-अपीलार्थी द्वारा और दूसरा फुसा, प्रतिवादी 3 द्वारा। विक्रेता के बेटे द्वारा लाए गए मुकदमे को समय-प्रतिबंध के रूप में खारिज कर दिया गया था, जबकि फुसा के मुकदमे को बाद में तय किया गया था। अपने पूर्व-मुक्ति मुकदमे को खारिज करने के बाद, अमर चंद ने सीमा शुल्क के तहत सामान्य घोषणात्मक मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि भूमि पैतृक थी और बिक्री विचार और कानूनी आवश्यकता के लिए नहीं होने के कारण, विक्रेता की मृत्यु के बाद उसके प्रत्यावर्ती अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा। उस मुकदमे में, उन्होंने प्रतिवादी 3, फुसा द्वारा प्राप्त पूर्व-मुक्ति डिक्री पर भी हमला किया। इस घोषणात्मक वाद का फुसा ने इस आधार पर विरोध किया था कि चूंकि अमर चंद वादी का पूर्व-मुक्ति का वाद खारिज कर दिया गया था, इसलिए उन्हें उनके द्वारा लाए गए बाद के घोषणात्मक वाद को बनाए रखने से रोक दिया गया था। ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय कोर्ट, लाभ सिंह बनाम गोपी और अन्य, गुजर बनाम औलिया और अन्य, और माउंट में प्रतिपादित नियम का पालन करते हुए। आलम खातून बनाम हयात खान ने आपत्ति स्वीकार कर ली और मुकदमे को खारिज कर दिया। अमर चंद वादी ने इस न्यायालय में एक नियमित दूसरी अपील को प्राथमिकता दी, जो हमारे विद्वान भाई, एस. सी. मित्तल, जे., के समक्ष सुनवाई के लिए आई, जो अकेले बैठे थे। अपीलार्थी के वकील द्वारा विद्वत एकल न्यायाधीश के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि न तो न्यायिक निर्णय और निरोध के सिद्धांत, जिन पर (अधिवक्ता के अनुसार) न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय आधारित हैं, और न ही आदेश 2, नियम 2, सिविल प्रक्रिया संहिता का सिद्धांत, अमर चंद वादी के बाद के घोषणात्मक वाद को रोक सकता है। इस विवाद के समर्थन में वकील ने मुहम्मद दीन बनाम रहीम गुल और एक अन्य मामले में पंजाब मुख्य न्यायालय के खंड पीठ के फैसले का हवाला दिया।

(3) विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि विद्वान न्यायाधीशों का ध्यान, जिन्होंने नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा भरोसा किए गए मामलों का फैसला किया था, मुहम्मद दीन के मामले में आमंत्रित नहीं किया गया था। दो डिवीजन बेंच के फैसलों के बीच जो टकराव प्रतीत होता था, उसके समाधान के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश ने मेरे लॉर्ड द चीफ जस्टिस को एक पूर्ण बेंच के गठन के लिए प्रेरित किया। इस तरह यह मामला हमारे सामने आया है।

(4) श्री एन. के. सोधी का तर्क है, जैसा कि उन्होंने एकल न्यायाधीश के समक्ष किया था, कि लाभ सिंह के मामले के नेतृत्व में निर्णयों की कड़ी, इस धारणा पर आधारित है कि पूर्व-प्रवर्तन के लिए एक वाद की मात्र स्थापना बाद के घोषणात्मक वाद को आकर्षित करती है, जो कि एस्तोपल, रचनात्मक न्यायपालिका और आदेश 2, नियम 2, सिविल प्रक्रिया संहिता के बार को आकर्षित करती है। वे प्रस्ताव, तर्क को आगे बढ़ाते हैं, जिन्हें धारा 115, साक्ष्य अधिनियम और धारा 11 और आदेश 2, नियम 2, सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित उनकी पूर्व-आवश्यकताओं द्वारा आंका जाता है, मान्य नहीं हैं। यहां तक कि अगर यह माना जाता है-यह तर्क दिया जाता है-कि बेटे द्वारा पूर्व-छूट के लिए एक मुकदमे की स्थापना केवल बिक्री के लिए एक सहमति का गठन करती है, तो यह भी, बिना इस बात के सबूत के कि विक्रेता ने अपनी स्थिति को इस तरह के विश्वास पर अपने नुकसान के लिए बदल दिया है, एक रोक नहीं लगा सकता है। अधिवक्ता के अनुसार न्यायनिर्णायक का बार काम नहीं कर सका क्योंकि वादी की क्षमता, इसमें शामिल मुद्दे और दो मुकदमों में मांगी गई राहत काफी भिन्न हैं, जबकि पूर्व वाद में, वादी ने मूल सौदे के प्रतिस्थापन के लिए अपनी व्यक्तिगत स्थिति में मुकदमा दायर किया, विक्रेता के स्थान पर, बाद के मुकदमे में, वह प्रतिनिधि क्षमता में, पूरे प्रत्यावर्ती निकाय की ओर से, बिक्री से बचने का प्रयास

करता है। तर्क की समानता पर, यह आग्रह किया जाता है कि बाद के वाद को आदेश 2, नियम 2, सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा वर्जित नहीं किया जाएगा।

(5) श्री सोधी द्वारा प्रचार किए गए विवाद, हालांकि आकर्षक प्रतीत होते हैं, जैसा कि बाद की चर्चा से पता चलेगा, हमारे सामने निर्धारण के लिए मामले पर गलत दृष्टिकोण का परिणाम है। वे इस धारणा पर आगे बढ़ते हैं कि लाभ सिंह के मामले में नियम, उपरोक्त कानूनों में निहित रोक-टोक और न्यायिक आधार के तकनीकी सिद्धांतों की व्याख्या से अधिक कुछ नहीं है। हालाँकि, यह धारणा सही नहीं है।

(6) जिस परिसर पर लाभ सिंह के मामले में नियम स्थापित किया गया है, उसकी सराहना करने के लिए, पैतृक संपत्ति के अलगाव को रोकने के लिए, प्रथा के तहत, एक प्रत्यावर्तक के अधिकार की प्रकृति के बारे में स्पष्ट विचार प्राप्त करना आवश्यक है। ऐतिहासिक रूप से, यह अधिकार संयुक्त स्वामित्व के अज्ञेयवादी सिद्धांत का एक उत्पाद है, जिसके अनुसार स्वामित्व इकाई जनजाति थी। जनजाति का व्यक्तिगत सदस्य केवल भूमि के उस हिस्से को हड़पने का हकदार था जो वास्तव में उसके और उसके परिवार द्वारा खेती की गई थी, और उस हिस्से में एक हिस्सा जो अभी भी संयुक्त प्रबंधन के तहत था। 'ऐसे समुदाय में, स्वामित्व का अधिकार और आम संपत्ति को स्थायी रूप से अलग करने की शक्ति पूरे निकाय में निहित थी'। समय के साथ, जैसे-जैसे इन समुदायों ने अपने आदिम चरण को पीछे छोड़ दिया, आम भूमि या इसका एक बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से परिवारों के बीच विभाजित हो गया और परिवार स्वामित्व की इकाइयाँ बन गए। हस्तांतरण या उप-विभाजन के परिणामस्वरूप पारिवारिक भूमि व्यक्तियों के कब्जे में आ गई, लेकिन ऐसे किसी भी व्यक्ति के हाथों में पैतृक अचल संपत्ति के संबंध में सामान्य पूर्वज के सभी वंशजों में एक अवशिष्ट हित मौजूद था, भले ही उनमें से कुछ के धारक के उत्तराधिकारी होने की संभावना कुछ समय के लिए बहुत दूर थी। "कब्जा करने वाले स्वामी को (पैतृक अचल) संपत्ति में पूर्ण या एकमात्र हित और इसे निपटाने की शक्ति के रूप में नहीं माना जाता था, ताकि उन लोगों की अपेक्षाओं को विफल किया जा सके जिन्हें अवशिष्ट हित माना जाता है और जो संपत्ति लेंगे यदि मालिक की मृत्यु हो जाती है। (रो की टिप्पणियों के अनुसार, जे. बाद में सर चार्ल्स रो पर-गुजर बनाम शाम दास में। मूल रूप से, सामान्य पूर्वज के सभी प्रत्यावर्तकों को, हालांकि, दूरस्थ, स्वामित्व वाले मालिक द्वारा पैतृक भूमि के अनावश्यक अलगाव को रोकने का अधिकार था।

(7) जबकि इस कालातीत सिद्धांत के अधिकांश न्यायिक इतिहास के जीवाश्मों में पारित हो गए हैं, इसके कुछ उत्पाद कुछ हद तक क्षीण रूप में आज तक जीवित हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, पंजाब प्रथा (प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति) अधिनियम, 1920 को पारित करने के लिए विधानमंडल के कदम उठाने से बहुत पहले, अलगाव को चुनौती देने के लिए प्रत्येक प्रत्यावर्तक का अधिकार, चाहे वह कोई भी हो, बहुत सीमित हो गया था। सुविधा, समानता और सार्वजनिक नीति पर विचार और बदलती परिस्थितियों के आलोक में प्रथा की व्याख्या करने की आवश्यकता का उन सिद्धांतों के विकास से कोई लेना-देना नहीं था जो आज तक जीवित हैं। यह ध्यान में रखते हुए कि एक प्रत्यावर्तक का अलगाव का विरोध करने का अधिकार नागरिक के अनुबंध की स्वतंत्रता के सामान्य अधिकार के खिलाफ है, न्यायालयों ने इसकी कोणीयता के इस नियम को छीन लिया है और इसे वैध सीमाओं के भीतर सीमित रखा है। (खुदा यार बनाम इमाम दीन में जे. जय लाई की टिप्पणियाँ देखें। इस प्रकार, पंजाब में सार्वभौमिक प्रथा के बचे हुए नियमों में से एक, जो न्यायिक निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला द्वारा दृढ़ता से स्थापित किया गया है, यह है कि पैतृक अचल संपत्ति के अलगाव पर आपत्ति करने वाला उचित व्यक्ति तत्काल प्रत्यावर्ती उत्तराधिकारी है; और यदि वह, सद्भावना से, अलगाव में सहमत होता है, तो यह लेनदेन को मान्य करता है और विचार की कमी और कानूनी आवश्यकता के आधार पर सामान्य पूर्वज के किसी भी वंशज द्वारा इसे प्रतिरक्षा रूप से हमला करता है।

इस सिद्धांत का सार रॉबर्टसन जे. ने लाभू बनाम एम. एस. टी. में स्पष्ट रूप से दिया था। निहाली, इस प्रकार हैः- "इसलिए हम पाते हैं कि अधिकांश मामलों में प्रथा ने एक ठोस और उचित सिद्धांत स्थापित किया है कि एक अलगाव जो एक बार विदेशी द्वारा खुले तौर पर और अच्छे विश्वास में किया गया था, और इसे लड़ने के लिए उस समय सक्षम लोगों द्वारा भी उचित और अच्छे विश्वास में स्वीकार किया गया था, उसकी अंतिमता होगी, और अन्य लोगों द्वारा चुनाव लड़ने के लिए खुला नहीं होगा जो बाद में ऐसी स्थिति में आ सकते हैं जो उन्हें उस समय

अलगाव का विरोध करने का अधिकार देता। संपार्श्विकों की सहमति से सभी आने वालों के खिलाफ स्थायी अलगाव को अच्छा बनाने का अधिकार पंजाब की प्रथा की सबसे आम विशेषताओं में से एक है।

(8) उक्त प्रस्ताव के समर्थन में पर्याप्त प्राधिकरण हैं कि पुरुष वंशजों की मान्य सहमति (रैटिगन के डाइजेस्ट ऑफ कस्टमरी लॉ के पैरा 59 के अनुसार) अलगाव से पहले, या समकालीन रूप से, या उसके बाद दी जा सकती है। (खुदा यार का मामला देखें। फकीर चंद बनाम एमएसटी में। बिशन देवी, एक डिवीजन बेंच जिसमें अब्दुल राशिद, कार्यवाहक C.J., और अचरु राम, जे. शामिल थे, ने कहा कि पैतृक संपत्ति के पिता द्वारा अलगाव के मामले में वंशजों की सहमति अलगाव को मान्य करती है और रैटिगन के डाइजेस्ट ऑफ कस्टमरी लॉ के पैरा 67 'रिमोट रिवर्सनर्स को इसे चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं देता है। सांता सिंह बनाम बंता सिंह में, एक पूर्ण पीठ (जिसमें अब्दुल राशिद, C.J शामिल हैं। महाजन और खोसला, जेजे।) विषय पर केस-लॉ की समीक्षा करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि दादा पैतृक अचल संपत्ति को अलग करते हैं और पिता अलगाव के लिए अपनी सहमति देता है, तो पोते को इसे चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

(9) बार में उद्धृत किए गए निर्णयों पर संक्षेप में ध्यान देने के लिए अब मंच तैयार किया गया है।

(10) लाभ सिंह के मामले में, के. एस. ने एम. एस. द्वारा भूमि की बिक्री के संबंध में पूर्व-छूट के अपने अधिकार को लागू करने के लिए एक मुकदमा दायर किया था। के. एस. का मुकदमा अंततः खारिज कर दिया गया क्योंकि वह अग्रिम राशि जमा करने में असमर्थ था। इसके बाद, एम. एस. ने अपनी शेष आधी भूमि को गिरवी रख दिया। के. एस. ने बंधक पर महाभियोग चलाने के लिए फिर से मुकदमा दायर किया। मुकदमे से समझौता किया गया था, जिसके अनुसार, के. एस. ने ब्याज के साथ बंधक राशि का भुगतान किया। एम. एस. की मृत्यु के बाद, के. एस. के पोतों ने एम. एस. द्वारा अलग की गई भूमि पर कब्जा करने के लिए मुकदमा दायर किया, इस आधार पर कि बिक्री अनावश्यक थी और उन्हें बाध्य नहीं करती थी। डिवीजन बेंच का निर्णय देते हुए, जे. चटर्जी ने ये स्पष्ट टिप्पणियां कीं: –

"हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि काहन सिंह ने मेहताब सिंह द्वारा बिक्री पर पूर्व-छूट के लिए अपना मुकदमा लाकर, आवश्यकता के अभाव या अन्य कारणों के आधार पर इसे चुनौती देने के अपने किसी भी अधिकार को छोड़ दिया, जो उसके द्वारा इसे अमान्य करने के लिए पर्याप्त था। इस तरह के मुकदमे ने एक धारणा को जन्म दिया जो निश्चित रूप से निर्णायक नहीं था, कि बिक्री आवश्यकता के आधार पर खराब नहीं थी, लेकिन। इसने अनिवार्य रूप से आवश्यकता के अभाव में इसे अलग रखने के सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया। हम यह भी सोचने के लिए तैयार हैं कि वादी अपने दादा की ओर से छूट के लिए बाध्य है।संपत्ति का उपभोग करने वाले व्यक्ति, या अलगाव पर आपत्ति करने के अधिकार के हकदार व्यक्ति को उस तरीके के बारे में निर्णय का एक निश्चित अक्षांश दिया जाना चाहिए जिसमें संपत्ति या अधिकार को दूसरों द्वारा आक्रमण या खतरे में डालने पर संरक्षित किया जाना चाहिए, और हमारी राय में उसके उत्तराधिकारियों और वंशजों को उसके द्वारा इस तरह की कार्रवाई से बाध्य माना जाना चाहिए। t यह असहनीय होगा, और न्याय के न्यायालय में कार्यवाही में सभी अंतिमता को समाप्त कर देगा, अगर यह अन्यथा था। इसे एक ठोस उदाहरण से सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट किया जा सकता है, मान लीजिए कि प्रथागत कानून द्वारा शासित एक भूमि मालिक पर अंतिम मालिक का संबंध होने और सह-उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उसके द्वारा धारण की गई भूमि के संबंध में मुकदमा चलाया जाता है। वह दावे को निर्विवाद समझता है और इसे स्वीकार करना सबसे अच्छा समझता है, और उसके खिलाफ एक डिक्री पारित की जाती है, और उसके बाद सफल दावेदार कई वर्षों तक भूमि रखता है। क्या उनके वंशजों या संपार्श्विक उत्तराधिकारियों को उनकी मृत्यु के बाद डिक्री की अनदेखी करने की अनुमति दी जानी चाहिए, और यह आरोप लगाया जाना चाहिए कि प्रवेश अनधिकृत था और भूमि के कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा करने के लिए संपत्ति की बर्बादी के बराबर था? यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो रेस जुडिकाटा के नियम में एक महत्वपूर्ण सीमा लागू की जाएगी। यदि काहन सिंह ने पूर्व-मुक्ति के लिए एक डिक्री प्राप्त की होती और कीमत के भुगतान पर संपत्ति की वसूली की होती, तो क्या वादी को इस

आधार पर डिक्री को दरकिनार करने की अनुमति दी जाती कि यह एक बेकार का कार्य था जिसने उसके अधिकारों को नुकसान पहुंचाया था? इससे क्या फर्क पड़ता है कि इस मामले में कोई डिक्री प्राप्त नहीं की गई क्योंकि खरीद-धन जमा नहीं किया गया था। इसलिये हम समझते हैं कि काहन सिंह की छूट वादी को बाध्य करती है जो इस कारण से वर्तमान दावा करने से वंचित है।

(11) जो ऊपर उद्धृत किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि जब विद्वान न्यायाधीशों ने "न्याय के न्यायालय में कार्यवाही में सभी अंतिमता को समाप्त करने वाली असहनीय स्थिति के बारे में बात की, जिसका परिणाम यदि वे अन्यथा मानते हैं, तो वे प्रथा के सदियों पुराने नियम से विचलित हुए बिना थे, जिसके अनुसार तत्काल प्रत्यावर्तक की सहमति पैतृक अचल संपत्ति के अलगाव को मान्य करती है, जिससे इसे रोक और छूट के न्यायसंगत और न्यायसंगत सिद्धांतों के अनुरूप एक गतिशील व्याख्या मिलती है।

(12) बार में किसी भी प्राधिकरण का उल्लेख नहीं किया गया है, और न ही मेरे संज्ञान में कोई आया है, जिससे लाभ सिंह के मामले में नियम को हटा दिया गया था। इसे गुजर बनाम औलिया में दोहराया गया था। इसके बाद किशन सिंह बनाम अमर सिंह में फिर से जय लाई, जे।

(13) माउंट आलम खातून बनाम हयात खान, एक मुसलमान ने दहेज के बदले अपनी पत्नी को कुछ संपत्ति उपहार में दी। पति की मृत्यु के बाद विधवा ने पुनर्विवाह कर लिया और उसके पति के भाई ने यह आरोप लगाते हुए पूर्व-मुक्ति के लिए एक मुकदमा दायर किया कि लेन-देन एक उपहार नहीं बल्कि एक बिक्री थी। मुकदमा खारिज कर दिया गया।- इसके बाद उन्होंने. घोषणा (प्रथा के तहत) के लिए एक मुकदमा लाया कि उसने विधवा के पुनर्विवाह के आधार पर संपत्ति का अधिकार हासिल कर लिया था और यह कि उपहार उसके खिलाफ अमान्य था। यह देखते हुए कि बाद का वाद धारा 11 के अधीन या सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2, नियम 2 के अधीन वर्जित नहीं था, न्यायाधीश दीन मोहम्मद ने, गुजर बनाम औलिया के अनुपात का अनुसरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि वादी को बाद के वाद में उपहार को चुनौती देने से वर्जित किया गया था क्योंकि पूर्व-मुक्ति के लिए वाद लाकर उसे कानून की दृष्टि में लेन-देन के लिए सहमति दी जानी चाहिए थी।

(14) इस श्रृंखला में अंतिम मामला सांता सिंह बनाम तारा दास है। यह पटियाला न्यायिक समिति के अध्यक्ष के रूप में सर जय लाई का निर्णय है। लाभ सिंह के मामले में नियम का पालन करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पैतृक अचल संपत्ति की बिक्री को पूर्ववत करने के लिए प्रत्यावर्तक द्वारा केवल मुकदमा दायर करना बिक्री की वास्तविकता और वैधता को स्वीकार करने के बराबर है और प्रत्यावर्तक बाद में विचार और आवश्यकता के अभाव के आधार पर बिक्री की वैधता को चुनौती देने से वंचित है।

(15) उपरोक्त संदर्भ से, यह स्पष्ट हो जाएगा कि उपर्युक्त मामलों में विद्वत न्यायाधीशों को प्रक्रियात्मक विधि के शुद्ध नियम के रूप में तकनीकी अर्थों में नहीं बल्कि ऐसे मामलों में पक्षकारों को नियंत्रित करने वाले पंजाब प्रथागत विधि की एक शाखा के रूप में उन सिद्धांतों को लागू करने के लिए निर्दिष्ट किया गया था। ये मामले प्रथा के सुव्यवस्थित सिद्धांत के सभी उदाहरण हैं जो तत्काल प्रत्यावर्तक की, विशेष रूप से पुत्र की, स्पष्ट रूप से या निहितार्थ द्वारा दी गई, चाहे अलगाव से पहले या समय पर या बाद में दी गई हो, पिता द्वारा पैतृक चल संपत्ति के हस्तांतरण को मान्य करता है और न केवल सहमति देने वाले व्यक्ति को बल्कि दूरस्थ प्रत्यावर्तकों को भी बाद में अलगाव को इस आधार पर चुनौती देने से रोकता है कि इसे अच्छे विचार और कानूनी आवश्यकता के लिए नहीं बनाया गया था।

(16) यदि लाभ सिंह के मामले में प्रतिपादित निरोध और छूट का सिद्धांत और उसका पालन करने वाले प्रथा के मूल नियम का हिस्सा हैं, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 या किसी अन्य कानून में निर्धारित तकनीकी मानदंडों के साथ उस सिद्धांत का परीक्षण करना सही दृष्टिकोण नहीं होगा। इस प्रकार विचार करने पर, यह स्पष्ट हो जाएगा कि मुहम्मद दीन के मामले में खंड पीठ, कोई विपरीत नियम निर्धारित नहीं करती है। आलम खातून का मामला, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बाद के वाद को न्यायिक आदेश के रूप में या आदेश 2, नियम 2, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वर्जित नहीं किया गया था।

(17) मुहम्मद दीन के मामले में, वादी ने अन्य लोगों के साथ संयुक्त रूप से पूर्व-मुक्ति के लिए एक मुकदमा दायर किया, जिसे अंततः खारिज कर दिया गया। इसके बाद, वे इस तरह से बेची गई भूमि के कुछ भूखंडों को बरामद करने के लिए दूसरा मुकदमा लाए, इस आधार पर कि यह उनका है न कि विक्रेता का। विद्वत न्यायाधीशों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दूसरा वाद (आदेश 2, नियम 2, सिविल प्रक्रिया संहिता के सिद्धांत पर) वादी द्वारा पूर्व वाद में भूमि के स्वामित्व का दावा न करने के कारण वर्जित नहीं था, पहला, क्योंकि दोनों वादों में वादी अलग-अलग क्षमताओं में कार्य कर रहे थे, क्योंकि पहले वाद में वे एक निजी और अनन्य शीर्षक का प्रतिपादन कर रहे थेः दूसरा, क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 (धारा 11 के स्पष्टीकरण IV के अनुरूप) में स्पष्टीकरण II में "विषय जिसे हमले का आधार बनाया जा सकता था और होना चाहिए था" शब्द यह दर्शाते हैं कि एक वादी संपत्ति के लिए अपने सभी अधिकारों का एक बार में दावा करने या उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं है।

(18) यह देखा जाएगा कि मुहम्मद दीन के मामले (4) में बाद का मुकदमा अमान्य बिक्री से बचने के लिए प्रथा के तहत प्रत्यावर्तक का मुकदमा नहीं था। यह शीर्षक सरलीकरणकर्ता के आधार पर था, अर्थात्, कि विक्रेता का सूट में भूखंडों में कोई स्वामित्व या हित नहीं था और इसके परिणामस्वरूप, उन भूखंडों की बिक्री एक शून्य थी, जो कानून की नजर में मौजूद नहीं थी। उस मामले में प्रथा के किसी भी नियम के लागू होने का कोई सवाल ही नहीं था।

(19) इस संबंध में, यह स्मरण रखा जा सकता है कि पैतृक अचल संपत्ति के पुरुष स्वामी द्वारा या उसकी जीवन संपत्ति की विधवा द्वारा उसकी शक्तियों से अधिक (या यहां तक कि हिंदू कानून के तहत) उसकी शक्तियों के तहत अलगाव पूरी तरह से शून्य नहीं है, बल्कि केवल प्रत्यावर्तकों द्वारा अमान्य है, जो (रफनागौड़ा अन्नागौड़ा बनाम भाऊसाब में प्रिवी काउंसिल के शब्दों में, 'या तो अकेले या एक निकाय के रूप में, इसे व्यक्त अनुसमर्थन द्वारा या उन कार्यों द्वारा जो इसे वैध या बाध्यकारी मानते हैं' से बचने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से वर्जित हो सकते हैं। जबकि मुहम्मद दीन के मामले में, वादी बाद के मुकदमे में आरोप लगा रहा था कि बिक्री पूरी तरह से शून्य थी, तत्काल मामले में, जिसमें से यह संदर्भ उत्पन्न हुआ है कि विचाराधीन बिक्री केवल शून्य थी।

(20) पूर्वगामी कारणों से, मैं इस पीठ को निर्दिष्ट प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दूंगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकांक्षा सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

सोनीपत(हरियाणा)